



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

No. 30]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2006/पौष 30, 1927

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2006/PAUSA 30, 1927

न्यायमूर्ति आर. एस. पाठक जांच प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2006

न्यायमूर्ति आर. एस. पाठक जांच प्राधिकरण (प्रक्रिया का विनियमन) आदेश, 2006

सा.का.नि. 33(अ).—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के संकल्प संख्या 8/35/2005-ई.

एस., तारीख 11 नवम्बर, 2005 के अनुसरण में, न्यायमूर्ति श्री आर. एस. पाठक, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश से गठित उक्त संकल्प में विनिर्दिष्ट सौंपे गए कृत्यों में उपदर्शित निश्चित लोक महत्व के कतिपय विषयों की असलियत का पता लगाने के लिए न्यायमूर्ति आर. एस. पाठक जांच प्राधिकरण नामित एक प्राधिकरण स्थापित किया गया है;

और उक्त संकल्प में न्यायमूर्ति आर०एस० पाठक जांच प्राधिकरण को, अपनी प्रक्रिया विनियमित करने के लिए, जिसके अंतर्गत अपनी बैठकों का समय नियत करने और यह विनिश्चय करने के लिए कि वे बैठक सावर्जनिक होंगी या नहीं, सम्मिलित हैं, सशक्त किया गया है ;

और जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 11 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने भारत के राजपत्र [असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii)] में अधिसूचना संख्या 1186, तारीख 11 नवंबर, 2005, यह निदेश देते हुए कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 के कतिपय उपबंध प्राधिकरण को लागू किए जाएं, प्रकाशित की है।

और न्यायमूर्ति आर०एस० पाठक जांच प्राधिकरण इसके द्वारा अपनी प्रक्रिया विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है :—

- प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

(1)

2. प्राधिकरण, अपनी बैठकें विज्ञान भवन एनेक्सी, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान पर, जो वह उपयुक्त और आवश्यक समझें, आयोजित करेगा।
3. प्राधिकरण का कार्यालय, साधारणतः केंद्रीय सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले राजपत्रित और घोषित अवकाश दिनों से भिन्न सभी दिन 9.00 बजे प्रातः से 5.30 बजे सायं तक कार्य करेगा। तथापि, प्राधिकरण ऐसे दिन कार्य कर सकेगा जो उसके लिए सुविधाजनक और समीचीन हों।
4. प्राधिकरण की कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी। तथापि, प्राधिकरण अपने विवेकानुसार, विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाहियों को हिंदी में संचालित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। जहां कार्यवाहियां हिंदी में संचालित की जाती हैं, वहां उसके साथ-साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद रखा जाएगा।
5. प्राधिकरण की कार्यवाहियां जनता के लिए खुली नहीं होंगी। तथापि, प्राधिकरण अपने विवेकानुसार कार्यवाहियों को किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों या किसी विनिर्दिष्ट विषय-वस्तु के संबंध में सार्वजनिक रूप से करने का निदेश दे सकेगा।
6. प्राधिकरण के कार्यालय परिसर में प्रवेश को, प्राधिकरण के सचिव से लिखित में पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करके विनियमित किया जाएगा। किसी व्यक्ति को, पहले पूर्वोक्त लिखित अनुज्ञा प्राप्त किए बिना प्राधिकरण के कार्यालय परिसर में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
7. जहां प्राधिकरण सार्वजनिक बैठकें करने का आशय रखता है, वहां परिसरों में आगंतुकों के प्रवेश को समय-समय पर इस निमित्त आवश्यक निदेश जारी करके विनियमित किया जा सकेगा।
8. किसी व्यक्ति को, प्राधिकरण की विनिर्दिष्ट लिखित अनुज्ञा के बिना प्राधिकरण की कार्यवाहियों का फोटो लेने, वीडियो टेप करने या टेप रिकार्ड करने या किसी इलैक्ट्रॉनिक मद या युक्ति की सहायता से रिकार्ड करने या इन्टरनेट या किसी अन्य माध्यम से किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप या शो/टेलीकास्ट को पुनः उत्पादित करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

9. प्राधिकरण को सभी संसूचनाएं, जब तक ऊपर लिखित पते में कोई परिवर्तन, यदि कोई हो, नहीं किया जाता है, नई दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय में प्राधिकरण के सचिव को लिखित में संबोधित की जाएंगी। प्राधिकरण मौखिक संसूचना को स्वीकार नहीं करेगा।
10. प्राधिकरण कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर –
 - (i) ऐसे विषयों से संबंधित किसी कथन को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए जांच की विषय-वस्तु से परिचित सभी व्यक्तियों को आमंत्रित करते हुए, किसी अधिसूचना को ऐसी रीति में, जो वह उपयुक्त समझे, प्रकाशित कराने के लिए जारी कर सकेगा। उक्त अधिसूचना में वह रीति उपदर्शित होगी जिसमें ऐसा कथन प्रस्तुत किया जाना है जिसके अंतर्गत उक्त कथन को प्रस्तुत करने की समयावधि सम्मिलित है;
 - (ii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे उसकी राय में जांच में सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, ऐसे विषयों से संबंधित, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्राधिकरण को कोई कथन प्रस्तुत करने के लिए एक सूचना जारी कर सकेगा।
11. ऊपर विनियम 10 के अधीन जारी की गई सूचना के उत्तर में दिए गए प्रत्येक कथन के साथ, कथन में उपदर्शित तथ्यों के समर्थन में कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया एक शपथपत्र लगा होगा। जहां प्राधिकरण को ऐसा प्रतीत होता है कि कथन में सभी सुसंगत तथ्य अंतर्विष्ट नहीं हैं, वहां प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति को, उसको ज्ञात सभी तथ्यों को पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए एक अतिरिक्त कथन प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा। प्राधिकरण, उक्त व्यक्ति को किन्हीं दस्तावेजों, वस्तुओं, सामग्रियों या चीज वस्तुओं को, जिसके अंतर्गत उक्त व्यक्ति के कब्जे में या उसके नियंत्रण में टेप और रिकार्ड या कोई अन्य इलैक्ट्रॉनिक मद या युक्ति सम्मिलित हैं, प्रस्तुत करने के लिए भी निदेश दे सकेगा।
12. प्राधिकरण का सचिव या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्राधिकरण का कोई अन्य पदधारी, प्राधिकरण की ओर से कोई दस्तावेज प्राप्त कर सकेगा और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए समनों और प्रत्येक अन्य आदेशिका पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत होगा।
13. प्राधिकरण द्वारा या अन्यथा आमंत्रित किए जाने पर फाइल किया गया कोई शपथपत्र (पत्रों) को किसी महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) या शपथ दिलाने के लिए विधि के अधीन सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।

14. कथन के साथ लगे किसी शपथपत्र को व्यक्तिगत रूप से या सचिव के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या कार्य घंटों के दौरान उसके द्वारा प्राधिकृत किसी पदधारी के माध्यम से अभिस्वीकृति सहित प्रस्तुत किया जा सकेगा या रजिस्ट्रीकृत, अभिस्वीकृति सम्यक् डाक द्वारा भेजा जा सकेगा। ई-मेल द्वारा किसी संसूचना को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक प्राधिकरण द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात नहीं किया जाता है।
15. प्राधिकरण को सभी संसूचनाएं, जिसके अंतर्गत कथन और उसके साथ लगे इस प्रकार फाइल किए गए शपथपत्र भी हैं, अंग्रेजी में होंगी। तथापि, यदि वे किसी अन्य भाषा में हैं तो उनके साथ उनका अंग्रेजी में सही अनुवाद लगा होगा जो संसूचना देने वाले व्यक्ति के शपथपत्र द्वारा सही अनुवाद होना सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित होगा।
16. प्रत्येक विषय-वस्तु से संबंधित सारांश तथ्यों के विवरण अलग-अलग पैराओं में होंगे।
17. यदि कथन में अंतर्विष्ट सूचना किसी दस्तावेज या अभिलेख, संक्षिप्त विशिष्टियों से ली जाती है तो उसे ऐसे दस्तावेजों की प्रकृति, उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण वाले विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उपदर्शित किया जाना चाहिए और ऐसी जानकारी के विनिर्दिष्ट स्रोत को प्रकट किया जाना चाहिए। यदि कथन का कोई भाग कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त सूचना पर आधारित है तो वह ऐसी जानकारी के विनिर्दिष्ट स्रोत को प्रकट करेगा।
18. कथन करने वाला व्यक्ति कथन के साथ ऐसे दस्तावेजों की एक सूची, जिस पर वह आश्रित होने का आशय रखता है, फाइल करेगा।
19. कोई कथन फाइल करने वाला व्यक्ति उसकी पांच प्रतियां फाइल करेगा। यदि कथन और/या शपथपत्र अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में फाइल किए जाते हैं तो उनके सही अनुवाद की उतनी संख्या में प्रतियां फाइल की जाएंगी।
20. कोई कथन करने वाला व्यक्ति कथन के साथ उन दस्तावेजों की मूल प्रति या अनुलिपियां, जिस पर वह आधारित है, फाइल करेगा। यदि ऐसा कोई दस्तावेज कथन करने वाले व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में नहीं है तो वह उस व्यक्ति की, जिसकी अभिरक्षा में वह है, संक्षिप्त विशिष्टियां, दस्तावेज की संक्षिप्त विशिष्टियों सहित प्रकट करेगा। यदि दस्तावेज कोई शासकीय अभिलेख है तो उस विनिर्दिष्ट विभाग या अधिकारी को, जिसकी अभिरक्षा और नियंत्रण में दस्तावेज है, उपदर्शित किया जाएगा।

21. शपथपत्र प्रथम पुरुष में लिखा जाएगा और अनुक्रमांकित संख्या में पैराओं में विभाजित किया जाएगा। आरंभिक पैरा में शपथपत्र के अभिसाक्षी का विवरण, उपजीविका, डाकीय और स्थायी पते का कथन होगा।
22. प्रत्येक शपथपत्र के अंत में निम्नलिखित रीति में एक सत्यापन होगा :—
- “यह सत्यापित किया जाता है कि ऊपर कथन/शपथपत्र के पैरा में दिए गए कथन मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार सही हैं और जो पैरा में दिए गए हैं, प्राप्त जानकारी और सही होने के विश्वास के अनुसार सही हैं”।
23. महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) या इस निमित्त सम्यक् रूप से गठित प्राधिकरण, जिसके समक्ष शपथ दिलाई जाती है, निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा :—
- “अभिसाक्षी द्वारा मेरे समक्ष शपथ ली गई जिसकी मेरे समाधानप्रद रूप में द्वारा पहचान की गई है या उसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। शपथपत्र को अभिसाक्षी को, जिसने इसे 2006 को पर सही होना स्वीकार करने के पश्चात् हस्ताक्षर किए हैं, पढ़कर सुनाया गया है।
मजिस्ट्रेट/प्राधिकरण की मुद्रा और हस्ताक्षर”
24. सभी कथनों की जांच पर, जो विनियम 10 के अधीन जारी की गई सूचनाओं के उत्तर में प्रस्तुत किए जाते हैं, प्राधिकरण, यदि न्याय के हित में आवश्यक समझता है तो कथन फाइल करने वाले किसी व्यक्ति से, मौखिक साक्ष्य देने और स्वयं को प्राधिकरण द्वारा आगे जांच के लिए पेश करने के लिए कोई शपथपत्र मंगा सकेगा।
25. प्राधिकरण, अपने विवेकानुसार प्राधिकरण द्वारा जारी की गई परिप्रेक्षण द्वारा जांच किए जाने वाले व्यक्तियों को और परिप्रेक्षण द्वारा या अन्यथा जांच के लिए कोई कमीशन परिदित करने या जारी करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। प्राधिकरण के कोई कथन लेखबद्ध करने के स्थान पर, प्राधिकरण, ऐसा व्यक्ति जिसके समक्ष कथन लेखबद्ध किया जाएगा, नियुक्त कर सकेगा।

26. साक्ष्य अधिनियम के तकनीकी नियम, उस रूप में, प्राधिकरण के समक्ष साक्ष्य को लेखबद्ध करने और उसकी ग्राह्यता को शासित नहीं करते हैं। तथापि, प्राधिकरण मुख्य रूप से, परिस्थितियों की अपेक्षानुसार औचित्य, साम्यता और न्याय के मूल सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा।
27. प्राधिकरण, उसके समक्ष पेश किए गए किसी कथन, शपथपत्र या अन्य दस्तावेज का लोप कर सकेगा या उसके किसी भाग को निकाल सकेगा या किसी दस्तावेज को वापस कर सकेंगा जो उसकी राय में असंगत, आक्रामक, अश्लील या कंलकात्मक है। कोई कथन, जिसके साथ कोई शपथपत्र न लगा हो या जो इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हों, प्राधिकरण द्वारा खारिज किए जा सकेंगे।
28. प्राधिकरण अपने विवेकानुसार कोई अन्वेषण करने के लिए किसी विभाग या अन्वेषण अभिकरणों के अधिकारियों की सेवा का उपयोग कर सकेगा।
29. प्राधिकरण, अपनी कार्यवाहियों में या अपने कृत्यों के अनुपालन में किसी अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की सहायता ले सकेगा।
30. प्राधिकरण, जांच से संबंधित विषयों से संबद्ध क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों के विचारों का निष्कर्ष निकाल सकेगा।
31. प्राधिकरण, जब कभी आवश्यक समझे, जांच के दौरान किसी समय इन विनियमों में फेरफार, उपांतरण, लोप या परिवर्धन कर सकेगा।
32. इन विनियमों के उपबंधों की बाबत किसी संदेह, विवाद या मतभेद की दशा में, प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा।

[फा. सं. 2/2/2006-जे आर एस पी आई ए]

प्राधिकरण के आदेश द्वारा
सुधा पिल्ले, सचिव

**JUSTICE R.S. PATHAK INQUIRY AUTHORITY
ORDER**

New Delhi, the 20th January, 2006

Justice R.S. Pathak Inquiry Authority (Regulation of Procedure) Order, 2006

G.S.R. 33(E).—Whereas in pursuance of a Resolution of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) Number 8/35/2005-E.S.; dated 11th November, 2005, an Authority named the Justice R.S. Pathak Inquiry Authority, consisting of Mr. Justice R.S. Pathak, former Chief Justice of India and former Judge of the International Court of Justice, has been set up to go into the root of certain matters of definite public importance as set out in the terms of reference specified in the said Resolution;

AND WHEREAS in the said Resolution the Justice R.S. Pathak Inquiry Authority has been empowered to regulate its own procedure including fixing the times of its sittings and deciding whether to sit in public or not;

AND WHEREAS in exercise of its powers under Section 11 of the Commissions of Inquiry Act, 1952, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) has published a notification in the Gazette of India [Extraordinary, Part II-Section 3-Subsection (ii)] No. 1186 dated November 11, 2005 directing that certain provisions of the Commissions of Inquiry Act, 1952 be made applicable to the Authority.

AND WHEREAS the Justice R.S. Pathak Inquiry Authority hereby makes the following order to regulate its procedure:

1. The Headquarters of the Authority shall be at Delhi.
2. The Authority shall hold its sittings at Vigyan Bhawan Annexe, Maulana Azad Road, New Delhi or at any other place as it may deem fit and necessary.

3. The office of the Authority shall ordinarily function from 9 A.M. to 5:30 P.M. on all days other than the gazetted and declared holidays observed by the Central Government. The Authority, however, may function on such days as may be convenient and expedient to it.
4. The proceedings of the Authority shall be conducted in English. However, the Authority may in its discretion, keeping in view the peculiar facts and circumstances, allow the proceedings to be conducted in Hindi. Where the proceedings are conducted in Hindi, its English translation shall take place simultaneously.
5. The proceedings of the Authority shall not be open to the public. However, the Authority may in its discretion direct the proceedings be held in public in respect of a particular person or persons or any specific subject matter.
6. Entry to the official premises of the Authority shall be regulated by prior permission to be obtained in writing from the Secretary to the Authority. No person shall be allowed to enter the official premises of the Authority without having first obtained the aforesaid written permission.
7. The entry of visitors to the premises where the Authority may intend to hold public sitting may be regulated by issuance of necessary directions in this behalf from time to time.

8. No person will be permitted to photograph, video tape or tape-record or record with the help of any electronic item or device or reproduce in any electronic form or show/telecast via the Internet or any other medium the proceedings of the Authority without the specific written permission of the Authority.
9. All communications to the Authority shall be addressed in writing to the Secretary of the Authority at its Head Quarters at New Delhi at the above address till a change, if any, in the address is notified. The Authority will not entertain any oral communication.
10. The Authority may at any stage of the proceedings:
 - (i) issue a notification, to be published in such manner as it deems fit, inviting all persons acquainted with the subject-matter of the inquiry to furnish to the Authority a statement relating to such matters as may be specified in the notification. The said notification shall indicate the manner in which such statement is to be submitted including the time period of submitting the said statement;
 - (ii) issue a notice to every person, who in its opinion should be given an opportunity of being heard in the inquiry, to furnish to the Authority a statement relating to such matters as may be specified in the notice.

189 GL/c6-3

11. Every statement made in response to the notice issued under Regulation 10 above shall be accompanied by an affidavit in support of the facts set out in the statement sworn by the person furnishing the statement. Where it appears to the Authority that the statement does not contain all the relevant facts, the Authority may direct such person to submit an additional statement making a full disclosure of the facts known to him. The Authority may also direct the said person to produce any documents, objects, materials or things including video tapes and records or any other electronic item or device in possession or in control of the said person.
12. The Secretary to the Authority, or any other official of the Authority duly authorized in this behalf, may receive any document on behalf of the Authority and shall be authorized to sign the summons and every other process issued by the Authority.
13. Any affidavit(s) filed on being invited by the Authority or otherwise, shall be attested by a Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate (1st class) or any other authority empowered under law to administer oath.
14. The statement accompanied by an affidavit may be presented under acknowledgement either in person or through a duly authorized representative to the Secretary or an official

- authorized by her during office hours or may be sent by Registered, acknowledgement due post. No communication by e-mail shall be entertained unless specifically permitted in writing by the Authority,
15. All communications to the Authority, including statements and the accompanying affidavits so filed, shall be in English. However, if the same are in any other language, they shall be accompanied by a true translation of the same in English, duly authenticated by an affidavit of the person making the communication to be such true translation.
 16. Statements of material facts relating to each subject matter shall be in separate paragraphs.
 17. If information contained in the statement is derived from any document or records, the precise particulars and nature of such documents, the specific person in custody or control thereof should be indicated and specific source of such information should be disclosed. If any part of the statement is based on information received by the person making the statement, he shall disclose the specific source of such information.
 18. The person making the statement shall file along with the statement a list of such documents on which he intends to rely.

19. The person filing a statement shall file five copies thereof. If the statements and/or affidavits are filed in any language other than English, the same number of copies of its true translation shall be filed.
20. A person making a statement shall file along with the statement the originals or copies thereof of the documents upon which he relies. If such a document is not in possession or control of the person making the statement, he shall disclose the precise particulars of the person in whose custody the same is available along with the precise particulars of the document. In case the document is an official record, the specific department or the officer in whose custody and control the document is shall be indicated.
21. The affidavit shall be drawn up in the first person and divided into paragraphs to be numbered consecutively. The opening paragraph of the affidavit shall state the description, occupation, postal and the permanent address of the deponent of the affidavit.
22. Each affidavit shall carry a verification in the end in the following manner:

“Verified that the statements made in paragraphs ____ of the above statement/ affidavit are true to my personal knowledge and those of paragraphs ____ are true to information received and believed to be true”.
23. The Metropolitan Magistrate or the Judicial Magistrate (1st Class) or the authority duly constituted in this behalf before

whom the affidavit is sworn, shall make the following endorsement:

“Sworn before me by the deponent who is identified to my satisfaction by _____ or is personally known to me. The affidavit has been read out in full to the deponent who has signed after admitting it to be correct, this _____ day of _____ 2006 at _____

Seal and signature of the Magistrate / Authority”

24. On examination of all statements that may be furnished in response to the notices issued under Regulation 10, the Authority may, if it considers necessary in the interest of justice, call upon any person filing a statement accompanied by an affidavit to give oral evidence and submit himself to further examination by the Authority.
25. The Authority may in its discretion allow a person to be examined by interrogatories issued by the Authority and delivered to him or issue a commission for examination by interrogatories or otherwise. Instead of the Authority recording a statement, the Authority may appoint a person before whom the statement shall be recorded.
26. Technical rules of the Evidence Act, as such, do not govern the recording and admissibility of evidence before the Authority. However, the Authority shall be broadly guided by the fundamental principles of fairness, equity and justice as required by the circumstances.

27. The Authority may delete or expunge any portion from any statement, affidavit or other document, or return any document presented to the Authority which, in its opinion is irrelevant, offensive, scurrilous or scandalous. Any statement not accompanied by an Affidavit or which does not conform to the requirements of these Regulations may be liable to rejection by the Authority.
28. The Authority may, in its discretion, utilize the services of any officers of any department or investigating agencies for conducting any investigation.
29. The Authority may take the assistance of an Advocate or Advocates in its proceedings and in the performance of its functions.
30. The Authority may elicit the view of persons having expertise in the field relating to matters pertaining to the inquiry.

31. The Authority reserves its right to alter, modify, delete, or add to, any of these Regulations at any time during the inquiry, as and when it considers necessary.
32. In case of any doubt, dispute or difference regarding the provisions of these regulations, the decision of the Authority in this regard shall be final and binding.

[F. No. 2/2/2006-JRSPIA]

By Order of the Authority

SUDHA PILLAI, Secy.